सामाजिक सेवा योजनाओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धनराशि का आवंटन

2475. **श्री राघवजी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक सेवाओं की किन-किन योजनाओ के लिये वर्ष 1996-97 के दौरान भारत सरकार को विश्व बैंक, किसी अन्य विदेशी संस्था अथवा देश द्वारा राज्यों में वितरण के लिये स्वीकृत की गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में योजना-वार कितना आवंटन किये जाने का प्रस्ताव है; और

ग) 31 दिसम्बर, 1996 तक प्रत्येक राज्य को कुल धनराशि आवंटित की गई है और बाकी बची धनराशि का योजना-वार भुगतान कब किया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाओं को विश्व बैंक/विदेशी संस्थाओल निदेशों द्वारा अनुमोदित किया गया है:—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	करार की तारीख	अनुदान/ऋण	31.12.96 तक संवितरण (करोड़ रुपए)
1.	पश्चिमी बंगाल ग्रामीण जलापूर्ति (जर्मनी)	5.7.96	2.74 मिलियन ड्यूश मार्क	शून्य
2.	बुनियादी स्वास्थ्य, महाराष्ट्र (जर्मनी)	23.7.96	20.00 मिलियन ड्यूश मार्क	शून्य
3.	कर्नाटक ग्रामीण जल एवं सफाई चरण-II (डेनमार्क)	1.10.96	36.00 करोड़ रुपये	.3.10
4.	तमिलनाडु ग्रामीण जल एवं सफाई, चरण-II (डेनमार्क)	1.10.96	33.00 करोड़ रुपये	0.90

RBI Prudential Norms

2476. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Asian age dated 11-2-1997 captioned "RBI prudential norms do the trick for Bank of India"; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) It is not correct to say that the Government stands to lose Rs. 327.14 crores due to return of capital of Rs. 93.47 crores which is wrongly presumed to have been divested at a premium of Rs. 35 per share. The Government has written down its investment in the capital of the Bank of India for adjustment of their losses. These adjustments have been matched by the receipts and recoveries on the capital accounts. These corrections in investments have been made to allow the bank to raise capital from the market.

In order to stregthen its capital base the bank has made a public issue of Rs. 675 crores which has been fully subscribed. Classification of advances is done by the Bank as per Reserve Bank of India guidelines and it has been certified by the Statutory Auditors.